उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–07(07/61)**

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सोमवार को 270 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 250 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 11 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1085 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2817 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 87 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने सोमवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने इस अभियान से जुडे हुए जल निगम, बीएसएनएल, लो.नि.वि., ऊर्जा व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन–जिन स्थानों पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है, उन स्थानों पर संबंधित विभाग अपने से संबंधित कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करें। जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि ध्वस्तीकरण किये गये स्थानों पर लगाये गये पीलरों पर जीयो–टैगिंग का कार्य तीव्रता के साथ किया जाए।

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य में विद्युत व लोक निर्माण विभाग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने निर्देश दिये कि रिस्पना से प्रिंस चौक व सर्वे चौक से रायपुर रोड स्थित डील फैक्ट्री तक जो भी सड़कों के चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है, इसका एस्टीमेट एम.डी.डी.ए., लोक निर्माण विभाग व ऊर्जा विभाग आपसी समन्वय के साथ तैयार करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

श्री ओमप्रकाश ने नगर निगम को निर्देश दिये कि वेंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, उनका एक रिकार्ड बनाया जाए, ताकि वेंडिंग जोन बनने के बाद उन्हें दुकानें पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आवंटित की जा सकें। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के कार्य में लगे हुए कार्मिकों के लिये जिस स्थान पर खाना बनाया जा रहा है। उस स्थान पर फूड इंस्पेक्टर की तैनाती भी की जाए, जो कि बन रह खाने की टेस्टिंग का कार्य सुनिश्चित करें।

अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य मुख्य सड़कों पर 25 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्य सड़कों पर 27 जुलाई, 2018 तक अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग की कार्यवाही पूरी की जाए।

बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, एसएसपी सुश्री निवेदिता कुकरेती, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–06(07/60)**

डोईवाला के आईटीआई भवन में कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र शुरू हो जाएगा। देश का अति आधुनिक संस्थान सीपेट (सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) उत्तराखंड में खुलेगा। इसकी आधारशिला मंगलवार को डोईवाला में केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक श्री अनंत कुमार और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रसायन एवं उर्वरक राव इंद्रजीत सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि होंगे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह से सोमवार को सचिवालय में मिलने आये केंद्रीय सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन श्री पी राघवेंद्र राव ने सीपेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ रुपये की लागत से डोईवाला में 10 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह संस्थान देश का अति आधुनिक संस्थान होगा। इससे उत्तराखंड में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मंगलवार को ही कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। आईटीआई में इस केंद्र का सत्र सितंबर माह से शुरू कर दिया जाएगा। इस केंद्र से प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को शत प्रतिशत प्लेसमेंट मिलेगा।

इस दौरान डीजी सीपेट प्रोफेसर (डॉ) एसके नाइक, केंद्रीय संयुक्त सचिव रसायन एवं पेट्रो रसायन अपर्णा एस शर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(07/59)

15वां वित्त आयोग करेगा अक्टूबर में प्रदेश का भ्रमण

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस वर्ष अक्टूबर में प्रदेश के भ्रमण पर आयेंगे। आयोग प्रदेश के वित्तीय आय–व्यय के साथ ही आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करेगा। 15वें वित्त आयोग को इस माह में राज्य के आर्थिक संसाधनों एवं वित्तीय आय–व्यय आदि का विस्तृत विवरण तैयार कर प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं सलाहकार वित्त श्री इंदु कुमार पाण्डे के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में, 14वें वित्त आयोग में हुए बेसिक परिवर्तन के कारण राज्य को हो रही कठिनाइयों का विस्तृत उल्लेख किया जाए। इस विवरण में अबतक राज्य को हुई आर्थिक हानि का आकलन कर इसकी भरपायी के लिये भी ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनावरण के साथ ही पर्वतों एवं ग्लेशियरों को भी इससे जोडने की बात इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। इससे ग्रीन बोनस का हमारा पक्ष भी मजबूत हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारी हिस्सेदारी केन्द्रीय करो में किस प्रकार और अधिक बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति, भागीरथी ईको सेंसटिव जोन, सेन्चुरीज, आदि के कारण अनेक जल विद्युत परियोजनां रूकी है। इससे हमारा ऊर्जा प्रदेश का सपना अधूरा रहने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी नुकसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की फ्लोटिंग पापुलेशन आपदा प्रभावित क्षेत्र आदि के कारण राज्य को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई का भी इसमें उल्लेख किया जाना भी उपयुक्त होगा। प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अपनी आय व्यय के अन्तर की भरपाई के लिये इसमें राज्य का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हिमांचल प्रदेश को मिल रही सुविधाओं तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले तथ्यों आदि का भी अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के सभी मानको का बिन्दुवार अध्ययन कर सभी तथ्यों का इसमें समावेश करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए।

इस संबंध में सलाहकार वित्त श्री इंदु कुमार पाण्डे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 15वें वित्त आयोग को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में सभी तथ्यों का समावेश किया जायेगा। आयोग से प्रदेश के संसाधनों की कमी के दृष्टिगत रेवन्यू डेफसिट ग्रांट उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का बडा भू–भाग वनावरण माउण्टेन ग्लेश्यिरों व सेन्चुरीज आदि के अधीन होने के कारण ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से रखी जायेगी।

बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्रीमती सौजन्या, डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव श्री एल.एन.पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(07/58)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई.टी पार्क में ड्रोन एप्लिकेशन अनुसंधान केन्द्र एवं साईबर सुरक्षा केन्द्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (एनटीआरओ) के सहयोग से ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थापित ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र भारत का पहला केन्द्र है, इसमें 10 दिन से 03 माह तक के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। इससे नौजवानों एवं तकनीकी शिक्षा में बड़ा फायदा होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पॉलीटेक्निक कॉलेजों का सेलेक्शन कर उनमें भी ड्रोन एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा प्रशिक्षित करेंगे। साईबर सुरक्षा केन्द्र की स्थापना से प्रदेश में साईबर क्राइम पर नजर रखने एवं अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी।

एनटीआरओ के अध्यक्ष श्री आलोक जोशी ने कहा कि साईबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन एप्लिकेशन स्मार्ट पुलिस का एक कान्सेप्ट है। देहरादून में साईबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर बनाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि साईबर सिक्योरिटी किसी एक संस्था के भरोसे नहीं चल सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। एनटीआरओ हमेशा पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार है। यह सेंटर आने वाले समय में ड्रोन एक्टिविटी एवं रिसर्च के लिए हब बनेगा।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि साईबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। साईबर क्राइम से बचने के लिए उत्तराखण्ड के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ड्रोन एप्लिकेशन अनुसंधान केन्द्र एवं साईबर सुरक्षा केन्द्र की स्थापना से उत्तराखण्ड को इस क्षेत्र में अच्छा अवसर मिला है।

ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उत्तराखण्ड सरकार एवं एनटीआरओ के बीच दिसम्बर, 2017 में एमओयू हस्ताक्षर किया गया। जिसमें ड्रोन अनुप्रयोग एवं अनुसंधान के लिये अत्याधुतिक केन्द्र की स्थापना ड्रोन संचालन हेतु उच्च तकनीकि के प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र की स्थापना, वन सर्वेक्षण, आपदा राहत एवं बचाव संचालन क्षेत्र में ड्रोन अनुप्रयोग को विकसित कर सामर्थ्य बनाने में तकनीकि सुविधा प्रदान करना है। ड्रोन अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से सरकार, छात्रों, पुलिस, वन, आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। ड्रोन प्रयोगशाला के माध्यम से कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बल संचालन हेतु रियलटाइम सैटलाइट सूचना एकत्रित करने, वनों पर नजर रखने, वन तस्करों पर निगरानी रखने तथा आपदा प्रबन्धन इत्यादि में मदद प्राप्त होगी।

साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण केन्द्र के लिये उत्तराखण्ड सरकार एवं राष्ट्रीय क्रिटिकल इनफॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, भारत सरकार (एन.सी.आई.आई.पी.सी.) के मध्य दिसम्बर–2017 में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया। महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना एवं कार्यस्थल पर साईबर स्वच्छता को बेहतर करने में सहयोग प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी कार्मिकों एवं छात्रों को साईबर अपराध जाँच तथा साईबर सुरक्षा की बारीकियों पर प्रशिक्षित किया जायेगा। इससे राज्य तथा देश में बढ़ते साईबर अपराध, साईबर धोखाधड़ी, साईबर धमकियों को पकड़ने में मदद मिलेगी तथा साथ ही राष्ट्र एवं राज्य में साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन एवं साईबर अपराध जाँच एवं फरेन्सिक में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस संचार प्रशिक्षण केन्द्र में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एवं एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया।

इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूडी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, श्री आर.एस.मीणा, सचिव आई.टी. श्री आर.के.सुधांशू, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्री अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(07/57)**

जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 (नयी संख्या–7) पर स्थित ''रिस्पना पुल'' का नाम ''स्वामी दयानन्द सरस्वती'' के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने बताया कि मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत देहरादून स्थित ''रिस्पना पुल'' का नाम परिवर्तन सम्बंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है।

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(07/56)**

सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरिद्वार जनपद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं के कियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतपाल महाराज, केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री देशराज कर्णवाल, श्रीमती ममता राकेश, श्री प्रदीप बत्रा, श्री संजय गुप्ता, श्री सुरेश राठौर, श्री फुरकान अहमद, श्री आदेश चौहान, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी व जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केबिनेट मंत्री ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में विपक्षी दल के विधायक भी सम्मिलित हुए। प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। हम सभी को मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की 25 घोषणाओं में 17 पूर्ण हैं जबकि 8 पर कार्य गतिमान है। रानीपुर की कुल 17 में 07 पूर्ण 05 गतिमान हैं। हरिद्वार क्षेत्र की 28 घोषणाओं में 11 पूर्ण 10 गतिमान हैं। भगवानपुर में 10 में से 10 पर कार्य गतिमान है। ज्वालापुर की 16 में 8 पूर्ण हैं जबकि 8 पर कार्य गतिमान है। झबरेड़ा की 5 में से 5 पूर्ण हैं। पिरान कलियर की 12 में से 02 पूर्ण व 10 गतिमान हैं। रूड़की की 20 में से 12 पूर्ण व 8 पर कार्य गतिमान है। खानपुर की 57 में से 42 पूर्ण हैं जबकि 13 पर कार्य गतिमान है। लक्सर की 29 में से 23 पूर्ण व 6 पर कार्य गतिमान है। मंगलौर की 9 में से 1 पर पूर्ण व 7 पर कार्य गतिमान है।

इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न विकास योनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की कियान्विति तय समय के अंदर धरातल पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि चिकित्सालयों में चिकित्सक राजकीय अवकाश व रात्रि के समय भी उपलब्ध हों।

हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आश्रमों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होती हैं वहां गृह कर मुक्त कर दिया गया है। धर्मशालाओं पर भी 3 गुना से कम करके 1 गुना कर दिया गया है। आदर्श नगर, विवेक विहार, में सीसी निर्माण के लिए 1 करोड़ 57 लाख रूपए स्वीकृत। काम प्रारम्भ हो चुका है। कुल 35 हैंडपम्प निर्माण के लिए टैंडर हो चुके हैं। हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना के रखरखाव के लिए 2 करोड़ 20 लाख की डीपीआर बना रहे हैं। नमामि गंगा में दीनदयाल पार्क से चंडी पुल तक आस्था पथ का निर्माण। वेबकोस से 6 करोड़ रूपए की योजना है। पी.एम. के.एस.वाई. के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए भारत सरकार को 531 लाख रूपए का प्रस्ताव भेजा है।हरिद्वार के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। लालजीवाला व पावनधाम में पार्किंग निर्माण का काम एडीबी के तहत किया जाएगा।आधुनिक शौचालय के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। वर्ष 2021 से पहले हरिद्वार में यातायात नियंत्रण के लिए हाईटैक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जल्द ही आंकलन तैयार कर लिया जाएगा। 10 हाई मास्ट लाईट हो चुकी हैं जबकि 10 और के लिए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। आरती दर्शन के लिए एलईडी स्क्रीन का टेंडर कर रहे हैं। खड़खड़ी शमशान घाट को एनएच 58 से जोड़ने के लिए 75 मीटर स्पान पुल का डीपीआर बनायी जा रही है। हरिद्वार में 10 प्रतिशत सीवरेज का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।अमृत योजना के तहत जलभराव की समस्या को दूर किया जाएगा। इनके अतिरिक्त कई आंतरिक मार्ग व नालियां निर्माण व अन्य कार्य भी हैं।

रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 40 हैंडपम्प की स्थापना की जा रही हैं। कार्य प्रगति पर है। बहादराबाद में डिस्ट्रीब्यूटरीज में लाईनिंग के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। शिवालिक नगरीय पेयजल योजना का नवीनीकरण 9 करोड़ 65 लाख रूपए की डीपीआर। वाल्मिकी बस्ती में नाला व टाईल्स निर्माण के लिए 485 लाख स्वीकृत। टिहरी विस्थापित भेल, शिव मंदिर सुभाषनगर सड़क चौड़ीकरण। मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। शिव मंदिर से बरसाती नाले तक नाली निर्माण। दर्शन लाल में सड़क–नाली पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ 17 लाख रूपए स्वीकृत। बहादराबाद में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। बहादराबाद में पेयजल के लिए नलकूप व नई पाईप लाईन की डीपीआर बना रहे हैं। ज्वालापुर–धीरवाली में कन्या इंटर कॉलेज में भवन निर्माण किया जाएगा। टीरा में नई पेयजल लाईन निर्माण की डीपीआर बना रहे हैं। रोशनाबाद से हरिद्वार मार्ग का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं। औरंगाबाद में नदी कटाव रोकने के लिए बंधों का निर्माण किया जाएगा। डीपीआर तैयार। शिवालिक नगर टिहरी विस्थापित क्षेत्र में पुल निर्माण।

भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपम्प की डीपीआर बन गई है। हसनपुर में सोलानी नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य नाबार्ड से किया जाएगा। बहेड़ी के सहादाबाद में पशु सेवा केंद खोला जाएगा। सरखेड़ी, इकबालपुर व मोहितपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा–कक्ष के निर्माण का आंकलन तैयार कर लिया गया है। भगवानपुर में बस अड्डा का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। विकास खण्ड कार्यालय राज्य योजना के तहत बनाए जाने पर सहमति बनी। भगवानपुर को नगर पालिका परिषद बनाया जाएगा।

ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के तहत खेड़ी–सिकरोढ़ा मार्ग पर छतिग्रस्त पुलिया का निर्माण की डीपीआर तैयार है। घाड़ क्षेत्र में 50 हैण्डपम्पों के निर्माण की डीपीआर बन चुकी है। रतमऊ नदी के बांए किनारे पर तटबंध निर्माण का कार्य

किया जायेगा। राजकीय इन्टर कौलेज मानूबांस में दो कक्ष कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार है। बुग्गावाला कन्या इंटर कॉलेजमें कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण का एक सप्ताह में एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। ज्वालापुर में आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा।डालूवाला–लारलवाला–धनोरी मार्ग पर पुल निर्माण की डीपीआर तैयार है। खेड़ी–सिकोहपुर–डांडा हसनगढ़ में सी.सी. मार्ग सितम्बर तक पूर्ण किया जायेगा। ज्वालापुर से वधवा शहीद तक सड़क किनारे नाले का निर्माण किया जायेगा। बुग्गावाला से दोड़बसी तक सड़क मार्ग निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण।

झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में बस अड्डे के लिए 10 दिन में भूमि का चयन कर लिया जायेगा। 25 हैण्डपम्पों के निर्माण की डीपीआर बन गई है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनौता में दो कक्षा कक्षों के निर्माण का वित्त को प्रस्ताव भेजा है। झबरेड़ा नगर पंचायत में लाईट लगाई जायेगी।

पीरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में 10 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे इसकी 15 दिन में स्वीकृति मिल जायेगी। जबकि नलकूप निर्माण स्वीकृत हो चुका है। पीरान कलियर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है। पीरान कलियर में पर्यटन सूचना केन्द्र बनाया जायेगा। एक सप्ताह में डीपीआर बना ली जायेगी। बस अड्डा के लिए शीघ्र ही भूमि का चयन कर लिया जायेगा।

रूड़की विधानसभा क्षेत्र में 85 मीटर स्पान के पुल की डीपीआर अगस्त तक तैयार हो जायेगी। मल्टीपल पार्किंग की डीपीआर तैयार हो चुकी है। रूड़की के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान। कार्य प्रगति पर है।

लक्सर में 50 हैंडपम्प लगने हैं इनमें से 25 स्वीकृत किए जा चुके हैं। क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन का नवीनीकरण की डीपीआर बन गई है। गंगा नदी में वायरक्रेट का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। रामपुर रायहट्टी गांव में बाढ़ सुरक्षा, नाबार्ड के तहत जल वितरण प्रणाली, जीआई सी निरंजनपुर में चारदीवारी व प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना है। पार्किंग के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। इसी प्रकार अनेक मार्गों की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है।

खानपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम करनपुर में जलभराव से निजात के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। नाबार्ड के तहत नलकूप व जल वितरण प्रणाली के लिए डीपीआर बन रही है। जीजीआईसी लंढौरा में दो कक्ष बनाए जा रहे हैं। 4 सिंचाई नलकूप की डीपीआर बनाई जा रही है। 20 हैंडपम्प का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शैलाबाग, कलसिया व ग्राम खानपुर में पेयजल टंकी बनाई जा रही है। लक्सर–लंढौरा रूड़की मार्ग का चौड़ीकरण का सर्वे किया जा रहा है। यहां के दो दर्जन से अधिक मार्ग अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 09 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(07/55)

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कुछ फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित विशेष अन्वेषण दल(एस.आई.टी.) तथा शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक सचिवालय सभागार में शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

शिक्षा मंत्री ने एस.आई.टी. द्वारा प्रचलित जांचों की प्रगति की समीक्षा की। चर्चा के दौरान उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद के 02 लिपिक संवर्ग कर्मियों पवन कुमार एवं मनोज चौहान द्वारा जांच में सहयोग न देने की शिकायत पर उनका स्थानातंरण तत्काल दूरस्थ जनपदों में करने निर्देश शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये। उन्होंने एस.आई.टी. द्वारा संस्तुत 20 प्रकरणों पर शीघ्र दोषी शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये तथा ऐसे प्रकरणों में नियुक्ति में दोषी नियोक्ता अधिकारी पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

ज्ञातव्य है कि गत् 05 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच किये जाने साथ–साथ इण्टर कॉलेज में कार्यरत कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने/सूचना प्राप्त होने की जांच एस.आई.टी. से करायी जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में वर्ष 2012 से 2016 तक नियुक्त किये गये 7047 शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित अभिलेख शिक्षा विभाग द्वारा एस.आई.टी. को उपलब्ध कराये गये, जिनमें से 10485 अभिलेख बाद सत्यापन प्राप्त हो चुके है तथा उक्त के अतिरिक्त विभिन्न माध्यम से प्राप्त 365 शिक्षकों से सम्बन्धित शिकायतों में से 161 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई है वर्तमान समय में शिक्षा विभाग से प्राप्त नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रभारी एस.आई.टी. सुश्री श्वेता चौबे ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया की कि 42 अध्यापकों के नियुक्ति सम्बन्धित अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही में से अब तक 20 प्रकरणों पर प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर चुकी है तथा 22 प्रकरणों पर विवेचना गतिमान है। प्रभारी एस.आई.टी. द्वारा बताया गया कि प्रमाण पत्र अभिलेखों के जांच के लिये कतिपय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा जांच शुल्क की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिये शुल्क माफ होनी चाहिए इस पर शिक्षा मंत्री द्वारा भी प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया गया तथा इस हेतु यदि धन की आवश्यकता हो तो वह शिक्षा विभाग से दिलाने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव शिक्षा डॉ.भूपिन्दर कौर औलख, महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर.के. कुंवर, अपर निदेशक शिक्षा श्री रामकृष्ण उनियाल, वीरेन्द्र रावत सहित शिक्षा विभाग तथा एस.आई.टी. के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।